

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल।

श्रम विभाग

देहरादून : दिनांक : 15 जुलाई-2008

विषय : वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु आयोजनागत पक्ष में बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं पुर्नवास
योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 2432/बजट-15-66/गु0/2008 दिनांक 26 मई 2008 के सर्वर्ष में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि आपके प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु आयोजनागत पक्ष में बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं पुर्नवास योजनान्तर्गत मानक मद संख्या 42- अन्य व्यय में प्राविधानित कुल रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आबंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3- व्यय करते समय Procurement Rules no. 8 में निर्धारित प्रक्रियानुसार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- राज्य में खतरनाक एवं गैर खतरनाक प्रक्रिया वाले प्रतिष्ठानों में चिन्हित बाल श्रमिकों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 दिसम्बर 1996 एवं बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के परिपालन में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित किया जाये, साथ ही चिन्हित बाल श्रमिकों के पूर्ण विवरण ट्रेकिंग कार्ड पर भी अद्यावधिक रखे जायें। प्रदेश में निरन्तर कमबद्ध रूप से सभी जनपदों में एक विशेष अभियान चलाया जाये, चिन्हित बाल श्रमिकों में से विभिन्न शिक्षण



संस्थाओं में प्रवेशित बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा (कापी, किताबें, ड्रेस, आदि) स्वास्थ्य, खेलकूद, छात्रवृत्ति, आदि की नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें, जिसकी समय-समय अद्यतन रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जायेगी। प्रश्नगत ट्रेकिंग कार्ड पर अद्यतन सूचनायें शासन को उपलब्ध कराये जाने तथा उक्त कार्ययोजना को शासन के अनुमोदनोपरांत ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2009 तक नियमानुसार पूर्ण उपयोग कर, व्यय की गयी धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु अनुदान संख्या-16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार, 01- श्रम, आयोजनागत, 103-सामान्य श्रम कल्याण 05- बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं पुर्नवास योजना-00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या 42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। यह आंबटन श्रमायुक्त उत्तराखण्ड के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : यूओ : 429/वि0अनु0-5/2008 दिनांक 10 जुलाई-2008 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

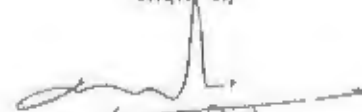
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 107 / VIII / 55-श्रम / 2006, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
- 3- वित्त अनुभाग-5
- 4- अपर श्रमायुक्त/उप श्रम आयुक्त, देहरादून।
- 5- एनआईसी, सचिवालय।
- 6- नियोजन विभाग
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।